CHANNEL SHOWDOWN: DTH VS BROADCASTERS HEATS UP

Tata Play and Airtel Digital TV have removed Sony and Zee channels from their base packs.

DTH operators Tata Play and Airtel Digital TV have removed Sony and Zee channels from their base packs over disputes related to pricing and the new regulatory framework under TRAI's NTO 3.0.

The move has ignited industry-wide debate over whether this tactic will help DTH players reclaim profit margins—or drive frustrated subscribers toward OTT platforms.

At the heart of the disagreement are the Reference Interconnect Offers (RIOs) issued by broadcasters under the New Tariff Order, leading to significant hikes in bouquet prices. DTH platforms, already grappling with shrinking ARPU (average revenue per user), high churn, and tight margins, are pushing back. The removal of popular channels is aimed at nudging users toward higher-value packs while reducing dependency on expensive broadcaster bouquets.

However, experts caution this could be a double-edged sword. While trimming base packs might improve short-term profitability, it also risks alienating price-sensitive users, especially in rural and semi-urban markets. Many of these users may either downgrade or disconnect entirely, opting instead for free DTH or OTT apps offering a cheaper, more flexible experience.

Broadcasters too stand to lose. Being dropped from base packs reduces passive reach, hurting both ad revenue and brand recall, particularly for FTA channels dependent on mass visibility. The Sony-Tata Play dispute has even reached the Bombay High Court, with Rs 300 crore in dues and subscription hikes at the core of the legal battle.

Airtel's quiet removal of Zee channels suggests more such conflicts may be brewing.■

चैनल मुकाबलाः डीटीएच बनाम प्रसारक गहराता जा रहा है

टाटा प्ले और एयरटेल डिजिटल टीवी ने अपने बेस पैक से सोनी और जी चैनल को हटा दिया है।

डीटीएच ऑपरेटर टाटा प्ले और एयरटेल डिजिटल टीवी ने मूल्य निर्धारण और ट्राई के एनटीओ **3.0** के तहत नये नियामक ढ़ांचे से जुड़े विवादों के चलते सोनी व जी चैनलों को अपने बेस पैक से हटा दिया है।

इस कदम ने उद्योग व्यापी बहस छेड़ दी है कि क्या यह रणनीति डीटीएच कंपनियों को लाभ मार्जिन वापस पाने में मदद करेगी या निराश ग्राहकों को ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर ले जायेगी।

असहमति के मूल में नये टैरिफ ऑर्डर के तहत प्रसारकों द्वारा जारी किये गये रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) हैं, जिससे बुके की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डीटीएच प्लेटफॉर्म, जो पहले से ही घटते एआरपीयू (प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व), उच्च परिवर्तन और तंग मार्जिन से जूझ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। लोकप्रिय चैनलों को हटाने का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उच्च मूल्य वाले पैक की ओर धकेलना और महंगे प्रसारक बुके पर निर्भरता कम करना है।

हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह दोधारी तलवार साबित हो सकता है। बेस पैक में कटौती से अल्पकालिक लाभ में सुधार हो सकता है लेकिन इससे कीमत के प्रति संवेदनशील उपयोगकर्ताओं, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों में, के अलग-थलग पड़ने का भी खतरा है। इनमें से कई उपयोगकर्ता या तो डाउनग्रेड कर सकते हैं या पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और इसके बजय मुफ्त डीटीएच या ओटीटी ऐप्स का विकल्प चुन सकते हैं जो सस्ता और अधिक लचीला अनुभव प्रदान करते हैं।

प्रसारकों को भी नुकसान होगा। बेस पैक से हटाये जाने से निष्क्रिय पहुंच कम हो जाती है, जिससे विज्ञापन राजस्व और ब्रांड रिकॉल दोनों को नुकसान पहुंचता है, खासकर उन एफटीए चैनलों के लिए जो व्यापक दृश्यता पर निर्भर हैं। सोनी-टाटा प्ले विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां **300** करोड़ रुपये का बकाया और सब्सक्रीप्शन में बढ़ोतरी कानूनी लड़ाई के केंद्र में है।

एयरटेल द्वारा जी चैनलों को चुपचाप हटाने से संकेत मिलता है कि इस तरह के और भी विवाद पैदा हो सकते हैं।■